**नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय में**

***<u>निर्णय की तिथि: 29 अगस्त, 2023</u>***

**<u>रि.या. (सि) 11437/2023</u>** व **<u>सि.वि. आवेदन 44513/2023</u>**

श्री अनिल कुमार ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सलमान खुर्शीद और श्री नरेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अल्जो के. जोसेफ, श्री प्रशांत झाजरिया, श्री सुनील कुमार और सुश्री सोम्या चतुर्वेदी, अधिवक्तागण।

बनाम

भारत निर्वाचन आयोग और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अंकित अग्रवाल खड़ा आर -1 के लिए अधिवक्ता।

श्री सुकुमार पट्टजोशी, सुश्री सुरुचि सूरी, स्थायी अधिवक्ता और श्री आकाश गुप्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री रैम कृष्ण श्री केएन राव, आर-2 से 13 के लिए अधिवक्ता।

**कोरम:**

**माननीय मुख्य न्यायाधीश**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला**

## निर्णय

**संजीव नरूला, जे (मौखिक):**

1. श्री अनिल कुमार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक इकाई, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ["डीपीसीसी"] के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ["ईवीएम"] और मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल्स ["वीवीपीएटी"] की प्रथम स्तर की जांच ["एफएलसी"] की तैयारी और संचालन के दौरान प्रतिवादी नंबर 2 - मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और प्रक्रिया के बारे में चिंता व्यक्त की है। 2024 में होने वाले लोकसभा के आगामी आम चुनावों में उपयोग के लिए इरादा है।

2. भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करके, याचिकाकर्ता, इस जनहित याचिका ["पीआईएल"] के माध्यम से, अपनी शिकायत को निम्नानुसार चित्रित करता है:

2.1. 11 पर और 12 जुलाई, 2023 को, संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों ["डीईओ"] के कार्यालयों ने 2024 के आम चुनावों में उपयोग किए जाने वाले ईवीएम और वीवीपीएटी के लिए विभिन्न जिलों में

एफएलसी अनुसूची का विवरण देते हुए संचार जारी किया। इन नोटिसों के अनुसार, एफएलसी 15वां और 30वां जुलाई, 2023 का, सुबह 09:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक निर्दिष्ट स्थानों पर। सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों से अनुरोध किया गया था कि वे उक्त प्रक्रिया की निगरानी के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नामित करें। 2.2 प्रतिवादी नंबर 1 - भारत निर्वाचन आयोग ["ईसीआई"] द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार,[1]एफएलसी आमतौर पर लोकसभा के आम चुनावों से 180 दिन पहले या ईसीआई द्वारा निर्देशित अन्यथा शुरू होता है। इस प्रकार, एफएलसी सितंबर 2023 के दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाना चाहिए था। इससे ईसीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित होता, दोनों इरादे और निष्पादन में। इसके बजाय, एफएलसी प्रक्रिया को तीन महीने आगे बढ़ा दिया गया था।

2.3. एफएलसी प्रक्रिया के लिए अनुसूची को सूचित करने वाला संचार बुरी तरह से अपर्याप्त था। प्रचलित जनादेश के अनुसार, राजनीतिक दलों को एफएलसी के शुरू होने से कम से कम एक सप्ताह पहले सूचित किया जाना चाहिए। एफएलसी शुरू होने से पहले केवल दो दिन के नोटिस ने

[1] "ईवीएम और वीवीपीएटी (एफएलसी) की प्रथम स्तर की जांच पर निर्देश" शीर्षक दिनांक 30वां अगस्त, 2017 और 13वां सितंबर, 2022 [क्रमशः अनुबंध पी-2 और पी-3]।

राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों को निर्देश देने या प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के साथ व्यक्तियों को संलग्न करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया।

2.4. एफएलसी के अधीन ईवीएम और वीवीपीएटी के विशिष्ट विवरण की कमी को संबोधित करते हुए, याचिकाकर्ता ने 15वां जुलाई, 2023 ने डीईओ को पत्र लिखकर प्रासंगिक जानकारी मांगी थी। हालांकि, अवसर के बावजूद, डीईओ याचिकाकर्ता/डीपीसीसी द्वारा उजागर किए गए मुद्दों के प्रति अनुत्तरदायी बने रहे।

2.5. उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण गुप्त प्रतीत होता है और इसमें पारदर्शिता का अभाव है। ईवीएम और वीवीपीएटी से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों के अभाव में, राजनीतिक हितधारकों की भूमिका केवल प्रक्रिया के पर्यवेक्षक बनकर रह गई, जिससे पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर संदेह पैदा हो गया। पारदर्शिता की भावना में, यह आवश्यक है कि सभी हितधारकों को ईवीएम और वीवीपीएटी के विवरण के बारे में सूचित किया जाए ताकि वे एफएलसी के दौरान मशीनों की प्रभावी निगरानी और सत्यापन कर सकें।

2.6. संपूर्ण एफएलसी प्रक्रिया में विसंगति को उजागर करते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 से संपर्क किया *वीडियो* संचार दिनांक 03सड़क अगस्त, 2023, उनसे चल रहे एफएलसी को समाप्त करने का

अनुरोध करते हुए। जवाब में, प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता के आरोपों से असहमत था और उसके अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया।

2.7. निर्धारित प्रक्रिया से उपरोक्त विचलन इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, न्यायालय को ईसीआई को ईवीएम और वीवीपीएटी के लिए एफएलसी को फिर से शुरू करने का निर्देश देना चाहिए, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 से 13 [उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों] की हिरासत में हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आगे के निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों को पर्याप्त नोटिस प्रदान किया जाए, जिससे वे एफएलसी में सार्थक भागीदारी के लिए अपने प्रतिनिधियों को नामित कर सकें। उत्तरदाताओं के लिए ईसीआई द्वारा अपने उपर्युक्त नोटिस दिनांक 30 में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है$^{वां}$ अगस्त, 2017 और 13$^{वां}$ सितंबर, 2022। इस तरह का पालन हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता, पारदर्शिता और पवित्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।

3. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 से 13 का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुकुमार पट्टजोशी सबसे पहले बताते हैं कि राज्य चुनाव आयोग के प्रति निर्देशित याचिका के कथन गलत हैं क्योंकि उक्त

आयोग की लोकसभा आम चुनावों में कोई भूमिका नहीं है। फिर भी, उनका तर्क है कि एफएलसी प्रक्रिया ने समय-समय पर संशोधित एफएलसी पर ईसीआई के निर्देशों सहित मौजूदा मानदंडों का सख्ती से पालन किया। याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य पात्र हितधारकों को एफएलसी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के पक्ष को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को नहीं सौंपने का विकल्प चुना। इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि केरल, झारखंड और दिल्ली के तीन राज्यों में ईवीएम और वीवीपीएटी के लिए एफएलसी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अन्य पांच राज्यों में प्रक्रिया प्रगति पर है। अकेले दिल्ली में कुल 42,000 बैलेट मशीनों और 23,000 वीवीपैट की जांच की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित निर्देश, यदि दिए जाते हैं, तो संभावित रूप से पूर्व-निर्धारित चुनाव कार्यक्रम को पटरी से उतार सकते हैं।

*विश्लेषण और निष्कर्ष:*

4. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की गहन जांच और सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। चुनाव प्रक्रिया के व्यापक महत्व के प्रति सचेत, वह आधार जिस पर हमारा लोकतांत्रिक राष्ट्र खड़ा है, हम स्वीकार

करते हैं कि इस प्रक्रिया की पारदर्शिता या प्रभावकारिता के बारे में कोई भी चिंता हमारे अत्यधिक ध्यान की मांग करती है।

5. ईवीएम और वीवीपीएटी की पहले स्तर की जांच ईसीआई द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के दायरे में होती है। दिनांक 13 दिशानिर्देश/अनुदेशवां सितंबर, 2022, एफएलसी आयोजित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को स्पष्ट करें:

***"3. एफएलसी कब किया जाना है:***

*(a) ईवीएम और वीवीपीएटी की एफएलसी विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक आम / उप-चुनाव से पहले या किसी भी चुनाव में जहां ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग किया जाता है, किया जाएगा।*

*(b) ईवीएम और वीवीपीएटी की एफएलसी शुरू होगी:*

*(i) उप-चुनाव की स्थिति में रिक्ति होने के एक माह के भीतर।*

*(ii) राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन की दशा में कम से कम पी-120 दिन।*

*(iii) लोक सभा के साधारण निर्वाचन की दशा में अथवा आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कम से कम पी-180 दिन।*

*(पी-का अनुमान पिछले आम चुनाव के आधार पर लगाया जा सकता है)।*

*(c) एफएलसी पर्याप्त रूप से अग्रिम रूप से की जानी होती है ताकि सभी जांचें राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बिना किसी अनुचित जल्दबाजी के की जा सकें।*

*(d) **<u>ईवीएम और वीवीपीएटी के एफएलसी को, जहां तक संभव हो, चुनाव की अनंतिम घोषणा से तीन महीने पहले पूरा किया जाएगा</u>**. पिछली बार चुनाव की घोषणा को देखते हुए इसकी गणना की जा सकती है।*

***4. एफएलसी की अनुसूची:***

*(a) एफएलसी में जांचे जाने वाले ईवीएम और वीवीपीएटी की संख्या के आधार पर, सीईओ/डीईओ ईवीएम निर्माताओं (बीईएल और ईसीआईएल) के परामर्श से ईवीएम के एफएलसी के लिए एक अनुसूची तैयार करेंगे।*

*(b) छुट्टियों सहित सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक एफएलसी का समय सुनिश्चित करें। किसी वैध कारण से किसी विशेष दिन पर समय या बंद के लिए किसी भी छूट अनुरोध के लिए, संबंधित सीईओ की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।*

[महत्त्व सन्निविष्ट]

6. एफएलसी प्रक्रिया के सर्वोत्कृष्ट पहलुओं में से एक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी है। इस आशय के लिए, दिशानिर्देश बताते हैं:

***"5. एफएलसी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा राजनीतिक दल:***

*(क) एफएलसी की अनुसूची जिला मुख्यालय में प्रत्येक राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को डीईओ द्वारा लिखित रूप में राज्य मुख्यालय में पक्षकारों को पृष्ठांकित उचित पावती और प्रति के साथ सूचित की जाएगी **जिले में एफएलसी शुरू होने से कम से कम 2 दिन पहले**. (ख) एफएलसी के दिन, दल के जिला अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।*

*(ग) डीईओ द्वारा एफआईसी हॉल में अनुलग्नक-1 में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर उनकी उपस्थिति के प्रतीक के रूप में प्रतिदिन लिए जाएंगे।*

[महत्त्व सन्निविष्ट]

7. एफएलसी एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की पारदर्शिता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रक्रिया को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ["बीईएल"] और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ["ईसीआईएल"] के प्रमाणित इंजीनियरों द्वारा निष्पादित किया जाता है और

इसमें कई महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं: (*एक*) डीईओ द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा मशीनों की प्रारंभिक निकासी, (*जन्म*बीईएल/ईसीआईएल के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया गया एक व्यापक दृश्य निरीक्षण, (*के आसपास*) फील्ड इंजीनियरों द्वारा पूर्व-प्रथम स्तर की जाँच इकाई का उपयोग करके कठोर कार्यक्षमता परीक्षण, और (*d*(ख) मॉक पोलिंग के लिए बीईएल/ईसीआईएल के प्राधिकृत इंजीनियरों द्वारा प्रतीक लोडिंग यूनिट के माध्यम से वीवीपीएटी में प्रतीक अपलोड करना।

8. कार्यक्षमता जांच के लिए उपर्युक्त कठोर कदमों से परे, हम ध्यान दें कि एफएलसी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, दिशानिर्देश नासिक सुरक्षा प्रेस द्वारा प्रदान की गई संशोधित गुलाबी पेपर सील का उपयोग करके नियंत्रण इकाइयों के कैबिनेट को सील करने का प्रावधान करते हैं। यह सीलिंग सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निम्नलिखित विधि के अनुसार की जाती है:

***9. ईवीएम की कंट्रोल यूनिट के प्लास्टिक कैबिनेट को संशोधित पिंक पेपर सील से सील करना***

*(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईवीएम की नियंत्रण इकाई को ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच के बाद नहीं खोला जा सके, नियंत्रण इकाइयों के मंत्रिमंडल को एफएलसी के समय उपस्थित राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नासिक सुरक्षा मुद्रणालय द्वारा आपूर्ति की गई संशोधित पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा। निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार:*

(i) *संशोधित गुलाबी पेपर सील में एक ही अद्वितीय के दो भाग / क्रम संख्या। सबसे पहले, सील को दो अलग-अलग गुलाबी कागज में विभाजित करें*
*जवानों।*

(ii) *गुलाबी पेपर सील से गम्ड पेपर को सावधानी से निकालें।*

(iii) *इन दो गुलाबी कागज की मुहरों को नियंत्रण इकाई के कैबिनेट के दो किनारों पर चिपकाया जाएगा जैसा कि आंकड़ों में दिखाया गया है:*

***संशोधित गुलाबी पेपर सील के साथ सील नियंत्रण इकाई***

(iv) *मुहरों के उचित निर्धारण के लिए, बीईएल और ईसीआईएल निम्नलिखित पर जोर देंगे:*

- *मुहरों की उचित हैंडलिंग।*
- *जिस सतह पर सील लगाने की आवश्यकता होती है वह साफ और धूल, गंदगी, पानी से मुक्त होनी चाहिए। रासायनिक और तेल।*
- *साफ उंगली के नाखूनों के साथ रिलीज लाइनर की सतह से सील को छीलना/हटाना।*
- *लागू सतह के लिए आवेदन उंगली के अंगूठे के दबाव (4-5 बार) हवा जेब की संभावना से बचने के लिए धीरे से किया जाना चाहिए, क्रीज.*
- *ईवीएम की सतह पर लगाई गई सील को आंशिक रूप से चिपकाया नहीं जाना चाहिए और हटाया और फिर से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।*

(v) *मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) में एफएलसी-ओके को चिह्नित करते समय क्यूआर-कोड स्कैन करके पिंक पेपर सील का विशिष्ट सीरियल नंबर दर्ज किया जाएगा।*

*(b) इंजीनियर और राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर उनके हस्ताक्षर के नीचे संक्षिप्तीकरण में पार्टी के नाम के साथ उपस्थित हों। उन्हें गुलाबी कागज की सील की क्रम संख्या नोट करने की अनुमति दें।*

*(c) ईएमएस में मशीनों के एफएलसी-ओके और एफएलसी-रिजेक्ट का अंकन दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए।*

*(d) में एक रजिस्टर बनाए रखें **अनुबंध-9** केन्द्रीय विश्वविद्यालय की विशिष्ट संख्या और गुलाबी कागज की सील के क्रम संख्या का उल्लेख करने के लिए और उनके हस्ताक्षर लेने और राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फोटोकॉपी प्रदान करने के लिए।*

*(e) एफएलसी-ओके बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी की सूची की फोटोकॉपी एफएलसी पूरा होने के बाद राष्ट्रीय इंड स्टेट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रदान करें और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि समाप्त होते ही सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी उनकी पावती लें।*

*(f) ईवीएम/वीवीपीएटी चालू करने के समय रजिस्टर की फोटोकॉपी की उपलब्धता सुनिश्चित करें।*

9. जैसा कि ऊपर उल्लिखित विस्तृत प्रक्रियाओं से स्पष्ट है, एफएलसी प्रक्रिया में न केवल बीईएल और ईसीआईएल के इंजीनियरों की सक्रिय भागीदारी शामिल है, बल्कि यह राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। यह समावेशी दृष्टिकोण पारदर्शिता की गारंटी देता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया निंदा से परे रहे। प्रतिनिधि केवल दर्शक नहीं हैं; वे कई स्तरों पर शामिल होते हैं, जिसमें सीलिंग तंत्र भी शामिल है, जो ईवीएम की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के रूप में कार्य करता है। उनके हस्ताक्षर प्रक्रिया की कठोरता और

पारदर्शिता को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, डीईओ की करीबी निगरानी, वेबकास्टिंग जैसे तकनीकी उपायों के साथ मिलकर, निगरानी की और परतों को सुनिश्चित करती है।

10. राजनीतिक दलों की भागीदारी, एफएलसी "ओके" मशीनों की स्वीकृति तक, लोकतांत्रिक भावना और प्रक्रिया की समावेशिता को रेखांकित करती है। हालांकि, डीपीसीसी ने विशेष रूप से दूर रहने का विकल्प चुना। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि एफएलसी अनुसूची को सूचित करने वाला डीईओ का नोटिस अपर्याप्त था, अदालत के पक्ष में नहीं है। ईसीआई के निर्देशों के पैराग्राफ 5 के अनुसार दिनांक 13वां सितंबर, 2022 में, डीईओ को एफएलसी शुरू होने से कम से कम दो दिन पहले प्रक्रिया की तारीखों को सूचित करना आवश्यक है। समय की संवेदनशीलता और चुनाव की अस्थायी घोषणा से तीन महीने पहले प्रक्रिया समाप्त करने के जनादेश को ध्यान में रखते हुए,[2] उनकी अनुपस्थिति के बावजूद, एफएलसी आयोजित किया गया था और तब से सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एफएलसी-ओके मतपत्र इकाइयों, नियंत्रण इकाइयों और वीवीपीएटी सूचियों को जारी करने के साथ समाप्त हो गया है।

11. प्रक्रिया के बारे में याचिकाकर्ता की आपत्तियां जांच के लिए निर्धारित ईवीएम और वीवीपीएटी की सूची के बारे में पूर्व सूचना की कथित कमी से

उपजी हैं। न्यायालय, निर्धारित निर्देशों और प्रक्रियाओं के अवलोकन पर, ऐसा कोई निर्देश नहीं पाता है जिसमें पूर्व अधिसूचना की आवश्यकता हो। पर्याप्त मजबूत प्रक्रियाएं हैं (जैसा कि ऊपर चित्रित किया गया है) जो पूर्ण पारदर्शिता का अनुभव करती हैं। सीलिंग प्रक्रिया - एफएलसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा - न केवल प्रकृति में प्रदर्शनकारी है, बल्कि सहभागी भी है, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर के माध्यम से अपनी स्वीकृति को चिह्नित करने की अनुमति मिलती है। नियंत्रण इकाइयों की अनूठी संख्या और गुलाबी कागज सील सीरियल नंबर जैसे विवरणों को रिकॉर्ड करने और वितरित करने के प्रावधान प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं, जिससे संदेह के लिए बहुत कम जगह बचती है। इस प्रकार, कठोर और पारदर्शी प्रक्रिया को देखते हुए, एफएलसी प्रक्रिया की विश्वसनीयता या सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ता के तर्क निराधार हैं।

12. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सलमान खुर्शीद द्वारा सीरियल नंबर प्रदान करने पर जोर देना पूरी एफएलसी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की राहत के लिए एक वैध आधार के रूप में नहीं खड़ा होता है। एफएलसी के दौरान डीपीसीसी की गैर-भागीदारी की न्यायालय की विशिष्ट जांच में सीरियल नंबरों की कमी के दोहराए गए दावे और उत्तरदाताओं से

उनके प्रतिनिधित्व दिनांक 15 के संबंध में गैर-उत्तरदायी रुख के अलावा कोई ठोस औचित्य नहीं मिला। जुलाई, 2023. चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए, याचिकाकर्ता का ध्यान प्रक्रियात्मक आशंकाओं के कारण अनुपस्थित रहने के बजाय सक्रिय भागीदारी पर होना चाहिए था। इसके अलावा, हमारे विचार में, जब एफएलसी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया राजनीतिक संस्थाओं से प्रतिनिधित्व और अवलोकन के अवसर प्रदान करती है, तो इन प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे सक्रिय रूप से भाग लें और प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करें। भागीदारी से दूर रहना और बाद में उसी प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठाना याचिकाकर्ता पर अच्छी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है।

13. इसके अलावा, याचिकाकर्ता की धारणा है कि एफएलसी को फिर से बुलाना होगा किसी भी समय की हानि का कारण नहीं बनना एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिसे न्यायालय को स्वीकार करना कठिन लगता है। ईसीआई सख्त समयसीमा पर काम करता है। देरी संभावित रूप से पूरी चुनावी प्रक्रिया को खतरे में डाल सकती है। ईसीआई के निर्देशों और आम चुनाव प्रक्रिया के उन्नत चरणों में उल्लिखित उपरोक्त चर्चा की गई समय-सीमा की विशिष्टता को देखते हुए, जैसा कि श्री पट्टजोशी द्वारा प्रकाश डाला गया है, प्रक्रिया की पुन: शुरुआत जैसे कोई भी परिवर्तन, एक महत्वपूर्ण प्रतिगमन होगा। अंततः, एफएलसी और पूरी चुनावी प्रक्रिया का उद्देश्य जनता की सेवा करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका विश्वास सुनिश्चित करना है। दिशानिर्देशों में सन्निहित सुरक्षा उपाय और जांच

एफएलसी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं। ईवीएम को सील करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल करना आपसी जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए समान अवसर दिया गया था। इस प्रकार, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी इसकी पवित्रता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे विचार से याचिका में ठोस आधार का अभाव है। नतीजतन, न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

14. पूर्वगामी कारणों से, वर्तमान याचिका को अन्य लंबित आवेदनों के साथ खारिज किया जाता है।

**संजीव नरूला, जे**

**सतीश चंद्र शर्मा, सीजे**

**अगस्त 29, 2023**
*डी.नेगी*

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*